



समकालीन परिप्रेक्ष्य में भारत-पाक संबंध: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. संगीता विजय^{1*}

दीपिका शर्मा^{2**}

अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दो राज्यों के द्विपक्षीय संबंधों के निर्धारण में उनके इतिहास, भूराजनीतिक संरचना, सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ, सीमा की प्रकृति, राजनीतिक स्थिरता आदि घरेलू कारकों तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत और पाकिस्तान संबंध भी इसका अपवाद नहीं है। भारत दक्षिण एशिया का हृदय स्थल है। दक्षिण एशिया के सम्पूर्ण देशों की सीमा भारत से स्पर्श करती है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 3287240 वर्ग किमी है। इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिन्दमहासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। विभाजन से पूर्व पाकिस्तान भारत का ही एक अंग था लेकिन अगस्त 1947 ऐसा वर्ष रहा जिस दिन भारत दो खण्डों में विभाजित हो गया। 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संसद के भारतीय स्वतंत्रता कानून के अनुसार पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। विभाजन के उपरांत नये भारत ने लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष राज्य और पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक गणतंत्रात्मक राष्ट्र घोषित किया। पाकिस्तान का क्षेत्रफल 796095 वर्ग किमी है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, दक्षिण में अरब सागर, पश्चिम में ईरान तथा पूर्व में भारत के जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात स्थित है। 1971 में बांग्लादेश का विभाजन पाकिस्तान से हुआ। पाकिस्तान का समस्त पूर्वी भाग बांग्लादेश के रूप में निर्मित हुआ। राजनीतिक दृष्टि से भारत और पाकिस्तान अलग-अलग राष्ट्र हैं लेकिन भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों की साझी भू-राजनीतिक पहचान है जिसको नकारा नहीं जा सकता। भारत और पाकिस्तान का समाज साझी विरासत को धारण करता है। दोनों का एक समान इतिहास है, लेकिन दोनों के रिश्ते पड़ोसियों की तरह सहज नहीं हैं और कश्मीर समस्या से शुरू होकर एक के बाद एक अनेक मुद्दे दोनों देशों के सम्बंधों को तनावपूर्ण बनाते हैं।

भारत-पाकिस्तान संबंध न केवल भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक संवेदनशील विषय है। भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों में उतार-चढ़ाव रहें हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में समकालीन युग में भारत-पाकिस्तान संबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर अध्ययन से स्पष्ट होता है कि द्विराष्ट्रवादी सिद्धान्त एवं

^{1*} एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, 511, रामानुज आवास, वनस्थली विद्यापीठ (राज.) मो.

07597965299 Email: vijay.sangeeta2020@gmail.com

^{2**} शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)

इसके परिणाम स्वरूप हुए भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण से उत्पन्न समस्याओं ने वर्तमान सम्बन्धों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। वहीं परिवर्तित परिस्थितियों ने दोनों राज्यों को नजदीक लाने के लिए प्रोत्साहित किया है। समय-समय पर द्विपक्षीय एवं बहु पक्षीय आधार पर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास पर किया गया। लगभग 7 दशकों के इतिहास में भारत और पाकिस्तान संबंध कई उतार-चढ़ाव के रहें हैं। भारत-पाकिस्तान के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक सम्बन्ध साझा रहने के उपरांत भी संबंध दुश्मनी, तनाव, ओर अविश्वास से ग्रस्त रहें है। भारत और पाकिस्तान ने स्वतंत्रता के बाद राजनयिक संबंधों की स्थापना की हैं लेकिन हिंसक विभाजन और क्षेत्रीय विवादों तथा 1947, 1965 तथा 1971 के युद्ध एवं आतंकी हमलों, तथा 1980 सियाचीन-ग्लेशियर का मुद्दा या कच्छ का रन का मुद्दा, 1989 में कश्मीर विद्रोह की गहनता, ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधारने के बजाय बिगाड़ दिया। यद्यपि भारत पाकिस्तान रिश्तों में सुधार लाने के लिए कई प्रयास भी हुए है। जैसे-शिमला शिखर सम्मेलन, आगरा शिखर सम्मेलन और लाहौर शिखर सम्मेलन इत्यादि।

1998 में भारत और पाकिस्तान के परमाणु परिक्षणों और 1999 के कारगिल युद्ध के बाद आए तनाव को कम करने के लिए कुछ उपाय भी किये गये-जैसे 2003 युद्ध विराम समझौता और दिल्ली लाहौर बस सेवा के माध्यम से तनाव को कम करने में कुछ सफलता प्राप्त हुई। हालांकि इन प्रयासों के दौरान 2001 में भारतीय संसद पर आतंकी हमले ने दोनों देशों को एक परमाणु युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। 2007 में समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट भी संबन्धों में महत्वपूर्ण मोड़ था। 2008 में फिर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा मुंबई हमला भारत पाकिस्तान के बीच चल रही शांति वार्ता के लिए गंभीर झटका साबित हुआ।

भारत पाकिस्तान के बीच मेल-मिलाप को कट्टरपंथी जिहादी तत्व, तालिबान, पाकिस्तानी अलकायदा, आईएसआई और सेना का एक बड़ा वर्ग होने नहीं देता। स्वतंत्रता के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ हमेशा शांति और दोस्ती की स्थापना के लिए गंभीर प्रयास किये लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भारतीय प्रधानमंत्रियों पं. नेहरु, मोरारजी देसाई, इंद्रकुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रयास किये है। अच्छे पड़ोसी के संबंध बनाने के लिए दोनों देशों की इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए ताकि दोनों के बीच शांति स्थापित हो सके।

भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध – एक विश्लेषण (1990 से लेकर अभी तक)

1985 में दक्षिण एशिया के सात देशों द्वारा आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग हेतु दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना था। भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य फैले हुए अविश्वास को देखकर ऐसा लगता था कि शायद यह एक ऐसा मंच है जहां पर इन दोनों के रिश्तों को सुधारा जा सके। लेकिन हालातों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शायद यह मंच भी इन दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने में नाकामयाब रहा। इसके बाद में भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों को इस प्रकार देख सकते है-

■ लाहौर घोषणा पत्र (1999)

शिमला समझौते के बाद भारत ने एक बार लाहौर घोषणा पत्र के जरिए दोनों देशों को बेहतर बनाने के प्रयास किया गया। फरवरी 1999 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर हुए जिसमें सभी मुद्दों को भूलाकर सम्बन्धों को बेहतर बनाने की कोशिश भारत की ओर से की गई। इसके अलावा नई दिल्ली से लाहौर से तक हफ्ते में दो बार सेवा-ए-सरहद की शुरुआत की

और कुछ मुख्य बातों पर चर्चाएं की गईं—वीजा नियमों को आसान बनाना,मिसाइल उड़डयन परीक्षणों की पूर्व सूचना देना,सुरक्षा निशस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता,यू.एन. चार्टर के सिद्धांतों और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता निभाना। इस घोषणा के तीन दिन बाद ही पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध छेड़ दिया।

▪ कारगिल युद्ध (1999)

पाकिस्तानी सैनिकों और कश्मीरी आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के कारगिल जिले में घुसपैठ की थी। भारतीय सेना ने इस समय कई ऑपरेशन भी चलाए। भारतीय सेना ने वायुसेना की मदद से टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी सेना को वापिस जाना पड़ा।

▪ आगरा शिखर वार्ता (2001)

प्रधानमंत्री वाजपेयी के निमंत्रण पर भारत-पाक शिखर वार्ता के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ 14 जुलाई 2001 को तीन दिवसीय यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुँचे। आगरा में सम्पन्न शिखर वार्ता को 16 जुलाई की रात चार दौर पूरे होने के बाद तब झटका लगा जबकि घोषणा पत्र पर सहमति के बिना राष्ट्रपति मुशर्रफ इस्लामाबाद रवाना हो गए। संयुक्त घोषणा पत्र में कश्मीर को मुख्य मुद्दे के रूप में शामिल करने के सवाल पर दोनों पक्षों में गतिरोध उभरकर आया।

▪ संसद भवन परिसर में आतंकी हमले (2001)

13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन परिसर में आतंकी हमले से भारत एवं पाकिस्तान के सम्बन्धों में गम्भीर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। हमले में पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तइबा व जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होने के प्रमाण मिलने के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाया। इस संदर्भ में इस्लामाबाद स्थिति भारतीय उच्चायुक्त विजय नाम्बियार को वापस बुलाने के अतिरिक्त नई दिल्ली व इस्लामाबाद स्थित पारस्परिक उच्चायोग में 50 प्रतिशत कटौती करने, दिल्ली-लाहौर बस सेवा व समझौता एक्सप्रेस रेलगाड़ी को बंद करने के निर्णय भारत सरकार ने किए हैं। पाकिस्तान ने भी नागरिक उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया।

▪ सीमा पर शान्त हुई गोलों की आग और वाजपेयी इस्लामाबाद में

पाकिस्तान के सम्बन्ध सुधारने की दिशा में एक बार फिर अपनी ओर से पहल करते हुए 22 अक्टूबर 2003 को भारत ने 12 सूत्री नए प्रस्तावों की घोषणा की। लोगों में मेलजोल बढ़ाना ही इन प्रस्तावों का सार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जमाली ने ईद के दिन से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा कर भारत से सकारात्मक जवाब देने की मंशा जताई। भारत ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की पाक की पेशकश मंजूर करते हुए सिचाचिन क्षेत्र से भी संघर्ष विराम की पेशकश की।

दिसम्बर 2003 में नई दिल्ली में दोनों देशों के अधिकारियों की नागरिक उड्यन सम्बन्धी बातचीत शुरू होने की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुशर्रफ ने भारतीय विमानों को पाक वायु सीमा से उड़ने की इजाजत देने की घोषणा की। दोनों देशों के बीच 1 जनवरी, 2004 से वायु सम्पर्क खुलने पर सहमति बनी। दोनों देशों में बस सेवा बहाल हो गई। भारत ने उसे बढ़ाने और रेल सम्पर्क बहाल करने के साथ मुम्बई कराची जलयान सेवा शुरू करने की पेशकश की। जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी बन्द सीमा पर ऐसी शान्ति कई वर्षों बाद बनी।

▪ सार्क सम्मेलन (2004)

जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने भाग लिया। तीन दिवसीय सार्क सम्मेलन के समापन पर 6 जनवरी 2004 को वाजपेयी एवं मुशर्रफ की मुलाकात के दौरान विदेश सचिव स्तर की वार्ता के आयोजन का फैसला किया गया। इसी सिलसिले में 18 फरवरी, 2004 को इस्लामाबाद में सम्पन्न तीन दिवसीय विदेश सचिव स्तरीय वार्ता शान्ति पहल के लिए तैयार 'बुनियादी रूपरेखा' पर सहमति बनी। वार्ता के पश्चात् संयुक्त

बयान में महत्वपूर्ण बिन्दु है –

- वार्ता के बाद जारी समग्र वार्ता प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई, जिसमें कश्मीर सहित आठ महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए 'रोडमैप' तैयार किया गया।
 - एक पांच सूत्री एजेण्डे की घोषणा की गई सिचाचीन, तुलबुल परियोजना, सरक्रीक, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी तथा आर्थिक-वाणिज्यिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान के प्रोत्साहन हेतु जुलाई 2004 में वार्ता होगी।
 - इस वार्ता से पूर्व मई 2004 में परमाणु विश्वास बहाली के उपायों पर विशेषज्ञ स्तर की तथा जून 2004 में मादक पदार्थों और अन्य वस्तुओं की तस्करी के बारे में वार्ता होगी।
 - पाकिस्तानी रेंजर के महानिदेशक और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के मध्य मार्च-अप्रैल में सीमा प्रबन्धन घुसपैठ एवं तस्करी रोकने पर वार्ता होगी।
 - दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा अगस्त 2004 में मुलाकात करके इस दिशा में हुई समग्र प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
- **क्रिकेट कूटनीति और राष्ट्रपति मुशर्रफ दिल्ली में (अप्रैल, 2005)**

क्रिकेट के बहाने भारत आए (16-18 अप्रैल, 2005) पाकिस्तानी परवेज मुशर्रफ ने तीन दिन के तूफानी दौर में भारत के साथ कश्मीर मसले पर असहमति के बावजूद दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सुधारने और विश्वास बहाल करने के विभिन्न उपायों को लागू करने की मंशा जताई।

18 अप्रैल, 2005 को दिल्ली के हैदराबाद हाऊस में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने साझा बयान में घोषणा की कि शान्ति प्रक्रिया को "अब वापस नहीं मोड़ा जा सकता और आतंकवाद को शान्ति प्रक्रिया की राह में आड़े नहीं आने दिया जायेगा।"

मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ की बातचीत में कुछ ऐसे ठोस मुद्दों पर प्रगति हुई जिन पर पहले दोनों देशों ने अडियल रूख अपना रखा था। ये मुद्दे हैं –श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा के फेरे बढ़ाने पर सहमति, पाकिस्तान ने आतंकवाद को शान्ति प्रक्रिया में बाधा नहीं पहुँचाने देने को कहा। संयुक्त आर्थिक आयोग गठित करने पर सहमति, मुम्बई और कराची में साल के अन्त तक वाणिज्य दूतावास खोलने, खोखरापार-मुनाबाओ रेल सम्पर्क तथा – पाकिस्तान चाहता है कि भारत जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर 450 मेगावाट की बिजली परियोजना (बगलीहार) का निर्माण रोक दे। दोनों नेता आपसी बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने पर सहमत हुए।

▪ **भारत-पाक बढ़ता सम्पर्क (2006)**

20 जनवरी 2006 को अमृतसर व लाहौर के बीच बहुप्रतीक्षित बस सेवा प्रारम्भ होते ही भारत का पाकिस्तान के बीच तीसरा सड़क मार्ग खुल गया। अमृतसर व ननकाना साहेब के बीच सब सेवा 24 मार्च 2006 से प्रारम्भ हुई है। अटारी-लाहौर समझौता एक्सप्रेस के बाद दूसरी रेलगाड़ी थार एक्सप्रेस का परिचालन 18 फरवरी, 2006 को हुआ। 14 जुलाई 2006 को मुम्बई ट्रेन विस्फोटो, जिनमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए, पहली बार भारत ने शांति वार्ता शुरू होने के बाद स्पष्ट संकेत दिया कि वार्ता खतरे में पड़ गई है। वस्तुतः मुशर्रफ ने जनवरी 2004 के अपने उस वादे को भी पूरा नहीं किया जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और उसकी सरजमी को भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे।

▪ **हवाना गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन(2006)**

14-15 सितम्बर, 2006 को हवाना में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में मनमोहन-मुशर्रफ मुलाकात के बाद यह तय किया गया कि दोनों देश संयुक्त रूप से आतंक निरोधी तंत्र विकसित

करेंगे तथा साथ ही दोनों देश जल्दी ही विदेश सचिव स्तर की वार्ता फिर से शुरू करेंगे। आतंकवादी घटनाओं और तमाम तरह की बाधाओं के बावजूद दोनों देशों की सरकारें जिस तरह से बस और रेल सम्पर्क बहाल करने का साहस दिखाया। उससे तीर्थाटन, पर्यटन, व्यापार, सांस्कृति आदान-प्रदान बढ़ावा मिला।

दिसम्बर 2006 में राष्ट्रपति मुशर्रफ ने जम्मू-कश्मीर समस्या के समाधान के लिए एक नया चार-सूत्रीय फार्मूला पेश किया जिसे भारत ने अस्वीकार्य बतलाया। अपने चार-सूत्रीय फार्मूले में कश्मीर की सीमाओं में कोई बदलाव न करने, वहाँ से सेनाएँ हटाने, दोनों देशों के संयुक्त निगरानी तंत्र के तहत वहाँ स्वशासन एवं सीमाओं व नियंत्रण रेखा को अप्रासंगिक बनाने की बात मुशर्रफ ने कही। फरवरी 2007 में ही दोनों देशों ने परमाणु हथियार के दुर्घटनावश इस्तेमाल के जोखिम में कमी लाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए।

कश्मीर में गोलमेज सम्मेलन (24-25 मई, 2006) श्रीनगर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में दो दिवसीय 24-25 मई 2006 को गोलमेज सम्मेलन सम्पन्न हुआ।

27 दिसम्बर, 2007 को पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। इस हत्या से पाकिस्तान के आधुनिकीकरण की ताकतों का गहरा धक्का पहुँचा। 25 मार्च 2008 को पाकिस्तान ने एक बार पुनः लोकतांत्रिक युग में उस समय प्रवेश किया जब लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित प्रधानमंत्री सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने शासन की बागडोर संभाली आम चुनावों के बाद आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ 'किंगमेकर' के रूप में उभरे जबकि राष्ट्रपति के रूप में मुशर्रफ की हैसियत कम हुई यानी सत्ता समीकरण में भारी बदलाव आ गया।

पाकिस्तान के राष्ट्रमण्डल से निलम्बन मई 2008 में समाप्त हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच 2010 तक गैस पाईप लाइन आरम्भ करने पर सहमति के आसार बने हैं।

18 अगस्त 2008 को राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने भारी विरोध और दबाव के बीच संसद में महाभियोग का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। मुश्किल यह है कि मुशर्रफ के बाद जिन शरीफ जरदारी पर पाक टिका है, वे खुद विपरीत ध्रुव हैं।

पाकिस्तान को यह सूचित किया गया कि 26 नवम्बर 2008 को मुम्बई पर आतंकी हमला पाकिस्तान से आए तत्वों द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की शर्म-अल-शेख में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन (जुलाई 2009) में इतर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के साथ भी वार्ता हुई मुम्बई में 26 नवम्बर के आतंकी हमले के पश्चात् भारत व पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं में मुलाकात का यह दूसरा अवसर था, इसके पूर्व पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ डॉ. मनमोहन सिंह की वार्ता जून 2009 में रूस में येकाटेरिनबर्ग में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन के इतर हुई थी। शर्म-अल-शेख में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री गिलानी ने भारतीय प्रधानमंत्री को आवश्यकता बताया कि उनका देश आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ी-से-कड़ी कार्यवाही करेगा तथा 26 नवम्बर के मुम्बई हमले के दोषियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगा। द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात् जारी साझा बयान में बलूचिस्तान को भी शामिल किए जाने के कारण विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की है। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों प्रधानमंत्रियों ने यह तय किया है कि दोनों देशों के विदेश सचिव आवश्यकतानुसार मिलते रहेंगे तथा अपनी बातचीत के निष्कर्षों से विदेश मन्त्रियों को अवगत कराते रहेंगे।

■ भारत-पाक वार्ता (2010)

इस्लामाबाद में सम्पन्न भारत पाक विदेश मंत्रियों की वार्ता (15-16 जुलाई 2010) से जैसी उम्मीद थी, परिणाम भी वैसा ही सामने आया। बातचीत को लेकर भारत सरकार भले ही कोई सार्थक परिणाम निकलने की आस लगाए बैठी हो। लेकिन देश की जनता को यह पता था कि ऐसी बातचीत से न पहले कोई हल निकला है और न ही भविष्य में निकलने वाला है। दोनों देशों के करोड़ों लोग भले ही अमन और भाईचारे की बात सोचते हों, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान कभी नहीं चाहेंगे कि दोनों देश दोस्ती की गाड़ी पर सवार हो। 16 जुलाई, 2010 को पाकिस्तान के विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी संवाददाता सम्मेलन में जिस तरह भारत के खिलाफ बोले, उससे इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता, कि पाकिस्तान बातचीत के अहम् मुद्दों की बजाय हमेशा उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करता है। जिनका कोई औचित्य नहीं है। दोनों मुल्कों के बीच आज कोई अहम् मुद्दा है, तो वह है आतंकवाद। जिस आतंकवाद से भारत वर्षों से झुलसता आ रहा है, वही आतंकवाद आज पाकिस्तान को भी अपने आगोश में ले चुका है। पाकिस्तान आए दिन अपने यहाँ होने वाले धमाकों में मरते लोगों की चिंता छोड़कर बातचीत में अगर फिर कश्मीर का राग अलापता है, तो समझ लेना चाहिए कि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आना चाहता। यदि पाकिस्तान को अपने यहाँ होने वाली तबाही से ज्यादा चिंता कश्मीर को लेकर है, तो साफ है कि वह दुनिया को सिर्फ यह दिखाने कि नाकाम कोशिश कर रहा है कि वह बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाना चाहता है। पाक विदेश मंत्री यदि भारत के गृह सचिव जी.के. पिल्लै के बयान की तुलना मुम्बई हमलों के प्रमुख मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भारत में विरोधी बयान से करता है तो जाहिर है कि वह बातचीत को भटकाने का प्रयास कर रहा है। दोनों देशों के बीच कोई मुद्दा है तो वो है आतंकवाद। पाकिस्तान इस समय अत्यन्त विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। आतंकवादी गुट, आईएसआई और अपराध जगत के अनेक ड्रग माफिया इस देश में फैले हुए हैं। आम आदमी की स्थिति वहाँ अत्यन्त भयावह है। इस दौर से सुरक्षित बाहर निकलना पाक के लिए तभी मुमकिन हो जब वहाँ का राजनीतिक नेतृत्व समय की नजाकत को समझते हुए सही दिशा में कदम उठाये ऐसे में भारत के लिए पाकिस्तान में लोकतांत्रिक ताकतों की मजबूरी एक सुखद खबर ही होगी।³

भारत की विदेश सचिव निरूपमा राव और पाकिस्तान के विदेश सचिव सलमान बशीर के बीच इस्लामाबाद में पारस्परिक विश्वास बहाली की दिशा में दो दिवसीय वार्ता (23-24, जून 2011) प्रारम्भ हुयी जिसमें दोनों देशों के हितों के संदर्भ में समस्त मुद्दों पर विचार-विमर्श की शुरुआत हुई। इसमें दोनों विदेश सचिवों ने शान्ति एवं सुरक्षा जैसे विषयों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जिसके अन्तर्गत उन्होंने स्वीकार किया कि भारत और पाकिस्तान आतंकवाद से ग्रस्त है जिसने दोनों देशों के विकास, शान्ति एवं सुरक्षा को बुरी तरह से प्रभावित किया है। दोनों ओर से यह प्रयास किये जा रहे हैं कि पारस्परिक विश्वास में आ रही कमी को दूर किया जाये एवं द्विपक्षीय सम्बन्धों को आगे बढ़ाया जाये। विदेश सचिव निरूपमा राव ने इस्लामाबाद में प्रेस कांफ्रेंस को संशोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी में भारत पाकिस्तान सम्बन्धों में "सैन्य संघर्ष की विचारधारा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।" (25 जून 2011, दी हिन्दू)

जम्मू व कश्मीर के प्रश्न पर भारत का रवैया स्पष्ट करते हुए विदेश सचिव निरूपमा राव ने कहा कि शांति एवं पारस्परिक विश्वास का निर्माण स्टेप-बाई-स्टेप किया जाना चाहिए। इससे यह निष्कर्ष स्वतः ही निकाला जा सकता है। कि दोनों देशों के बीच शांति स्थापना के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण हो सके। शान्ति वार्ता को पुनः जीवित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जिससे 26/11 से बंद समग्र वार्ता को पुनः पटरी पर लाया जा सके।

इसके अतिरिक्त नियंत्रण रेखा पर विश्वास निर्माण के उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है उसके लिए व्यापार एवं यात्रा व्यवस्थाओं में बेहतर सुधार एवं विस्तार की जरूरत है। फरवरी 2012 में भारत के वाणिज्य मंत्री आनन्द शर्मा की पाकिस्तान यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्धों को गतिशीलता प्रदान करना था। सितम्बर 2011 में वाणिज्य मंत्री शर्मा और पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री मखदूम अमीन फहीम ने द्विपक्षीय व्यापार को 2014 तक 6 बिलियन डॉलर करने की योजना की घोषणा की थी जो वर्ष 2010-11 के द्विपक्षीय व्यापार के 2.7 बिलियन डॉलर के आंकड़े से दुगुनी होगी। वर्ष 2015 तक यह द्विपक्षीय व्यापार 10 बिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है यदि दोनों देश अवरोधों के समक्ष चुनौति यह है कि वे सामरिक चिन्ताओं को किस प्रकार आर्थिक मुद्दों से अलग करें। उदाहरणार्थ, दोनों देश अफगानिस्तान में अपने-अपने प्रभाव को लेकर होड़ में लगे हुए हैं एवं एक दूसरे के इरादों पर विश्वास नहीं करते।

पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी ने अप्रैल 2012 में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों को हल किया जाना चाहिए ताकि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित किया जा सके। गिलानी ने चीन में आयोजित बोआओ फोरम फॉर एशिया को सम्बोधित करते हुये कहा है कि उनका देश भारत सहित अन्य देशों के साथ सम्बन्धों को सुधारने में जुटा है।

2013 पाकिस्तान ने भारत के साथ वार्ता जारी रखने की वकालात करते हुये कहा कि दोनों देशों के बीच कश्मीर, सियाचीन और वीजा जैसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा इर्दगिर्द पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का बार-बार उल्लंघन किये जाने को गंभीर चिन्ता का विषय बताते हुये भारत ने कहा कि पाकिस्तान की उकसाने वाली कारवाइ स्थिति में एक निर्णायक मोड़ है। पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर की बातचीत से पहले भारत ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच छह दशक पुराने मुद्दों के बड़े समाधानों की अपेक्षा ऐसे समय में नहीं करता जब देश कई उतार-चढ़ाव से गुजर रहा है। भारत की संसद जहां एक ओर पाकिस्तान को एलओसी पर सीजफायर के उल्लंघन तथा भारतीय सैनिकों की हत्या के लिए कड़ा संदेश दिया लेकिन फिर भी भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने संदेश में शांति और सहयोग के प्रति कटिबद्धता की बात करते हैं।

■ सर्जिकल स्ट्राइक (2016)

भारतीय सेना ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाली सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सीमा पार से तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तान ने ऐसी किसी भी गतिविधियों से इन्कार किया।

■ उरी हमला (2018)

भारतीय सेना ने भारतीय सेना के शिविर पर आतंकवादी हमले का प्रतिकार किया जिसमें 19 सैनिक मारे गये।

■ पुलवामा हमला (2019)

आतंकवादी समूह द्वारा सीआरपीएफ कर्मियों को ले जा रहे वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। जिसमें 40 सीआरपीएफ कर्मी मारे गये।⁴ भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापिस लेने और इसके आयात पर 200: कस्टम ड्यूटी लगाने से पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंधों का नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी पुलवामा आतंकी हमलों की निन्दा की गई।

⁴ प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका 2019

■ बालाकोट एयर स्ट्राइक

भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में शिविरों पर बम गिराकर हवाई हमला किया जिसमें 300 आतंकवादी मारे गये। पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ लिया। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई को पाकिस्तान की ओर से शांति संकेत माना जाता है। लेकिन समय के साथ-साथ भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्याएं और तनाव बढ़ता जा रहा है। क्योंकि भारत ने उन भारतीय नदियों के प्रवाह को रोकने का फैसला किया जो सिन्धु जल सन्धि के अनुसार भारत से सम्बंधित थे।

■ आर्टिकल 370 और 35ए का निरसन (2020)

5 अगस्त 2020 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक घोषणा की गई। जिसके तहत धारा 370 और 35ए जो जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, अस्तित्व में नहीं रहेगा। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को भी शामिल किया गया। पाकिस्तान के द्वारा भारत के इस कदम का विरोध किया गया। पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी द्विपक्षीय सम्बंधों को निलंबित कर दिया।

लेकिन अगर कश्मीर की समस्या को देखें तो यह एक ऐसा प्रश्न नजर आता है जो दोनों देशों के सम्बंधों को राष्ट्रवाद से भर देता है। फिर भी दोनों देशों के द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए समाधान ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन 21वीं सदी में भारत और पाकिस्तान के सम्बंधों को देखा जाए तो इनके बीच में सकारात्मक परिणाम आने की संभावना न के बराबर है। या या फिर कहें कि फिलहाल तो हालात ऐसे हैं कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते और खराब होने का माहौल बना हुआ है। इस समय रिश्तों में सुधार की गुंजाइश तो नहीं दिखती। भारत और पाकिस्तान में इस समय काफी गरमा-गरमी है अगर हम हालातों को और बिगड़ने से बचा सकें तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

2019 की घटनाओं पर अगर हम सही मायनों में नजर डालें तो कि 2020 का साल भारत और पाकिस्तान के सम्बंध के लिहाज से कैसा रहने वाला है। 2019 के शुरुआती महीनों में ही पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पुलवामा का आत्मघाती हमला किया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गये थे। इस घटना के बाद से ही दोनों देशों में सम्बंधों की गिरावट का दौर आरंभ हो गया था। इस हमले को देखते हुए, भारत जो काफी दशकों से अपने ऊपर बंदिश लगाए बैठा था, उनसे आजाद होते हुए, पलटवार के पाकिस्तान के बालाकोट पर हवाई हमले किये थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब भारत ने पीओके नहीं बल्कि पाकिस्तान की असली सीमा के भीतर घुसकर हमला किया था। पाकिस्तान ने भी भारत के इस हमले का जवाब दिया और ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच खुला युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन दोनों देशों ने युद्ध के करीब जाकर भी अपने पैरों को पीछे खींचना ही अच्छा समझा। लेकिन इन सब घटनाओं ने पाकिस्तान को यह एहसास जरूर करा दिया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अब कोई भी आतंकवादी कार्य किया जाता है तो भारत भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। अब आतंकवाद के नाम से पाकिस्तान भारत में और दहशत नहीं फैला सकता है।

अगस्त 2019 में हुए दूसरे क्रांतिकारी परिवर्तन ने तो पाकिस्तान को अंदर तक हिलाकर रख दिया। भारत की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली आर्टिकल-370 को करीब-करीब खत्म कर दिया। साथ ही कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में भी बदल दिया। इससे पाकिस्तान को भयंकर सदमा लगा। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के साथ सम्बंधों में जो गुंजाइश बची थी वो भी कहीं-न-कहीं भारत ने खत्म कर दी और भारत को यह उम्मीद थी कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान जरूर अपनी कुछ-न-कुछ

प्रतिक्रिया देगा और पाकिस्तान ने दुनिया भर में शोर मचाना आरंभ कर दिया कि भारत, कश्मीर में रक्तपात की तैयारी कर रहा है। ये बताकर वो दुनिया को डराना चाहता था कि इस वजह से लाखों लोग कश्मीर से पाकिस्तान चले जायेंगे और कश्मीर की आबादी की संरचना बदल जायेगी। इन सब घटनाओं के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ कूटनीतिक सम्बंधों का दर्जा हटाने का एलान कर दिया और पाकिस्तान में भारत के राजदूत को हटा दिया गया और पाकिस्तान ने भारत के साथ हर तरह का कारोबार बंद कर दिया। बालाकोट हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की जो 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' का जो दर्जा दिया था वो भी वापस ले लिया और पाकिस्तान पर शुल्क भी बढ़ा दिया गया। इन सब घटनाओं के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार नाममात्र का रह गया। लेकिन कुछ समय बाद ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भारत से व्यापार बंद करने का अपना ये फैसला बदलना पड़ा क्योंकि वहां के लोगों को यह एहसास हो गया था कि उन्हें दवाओं की सख्त जरूरत है जो इन्हें भारत से ही प्राप्त हो सकती है। इसके बावजूद कश्मीर पर भारत के कदम से आज की तारीख में भारत और पाकिस्तान के लोग नाममात्र के सम्बंध रह गये हैं। राजनयिक सम्बंध बहुत सीमित हो गया है और कूटनीतिक सम्बंध न के बराबर है।

आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान के भारत के करतारपुर गलियारे खोलने के फैसले को लागू किया। हालांकि पाकिस्तान के इस तरह के कदम उठाने से लोगों को लगा कि शायद दोनों देशों के सम्बंध कुछ सुधर जायेंगे, लेकिन नहीं, वो उसके माध्यम से खालिस्तान आन्दोलन में नई आग फूंकना चाहता था। करतारपुर गलियारा खुलने के बाद दोनों देश एक-दूसरे को सकारात्मक नजरिए से देखने के बजाय संदेह की दृष्टि से देखने लगे। अविश्वास के ऐसे माहौल के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने 2020 का आगाज किया है। दोनों देशों के सम्बंध अब एक-दूसरे को धमकियां देने के स्तर तक पहुंच चुके हैं। जब तक इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता में हैं तब तक भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनके जहरीले बयान आते रहेंगे।

भारत में इस वक्त सीएए-आरसी-एनपीआर को लेकर जो हल्ला मचा हुआ है पाकिस्तान इसमें भारत के लिए मुश्किलें पैदा करने की भरपूर कोशिश करेगा। पाकिस्तान हर मंच का उपयोग कश्मीर के मामले पर हल्ला मचाने के लिए करेगा। पाकिस्तान भारत में अब यही विरोध खासतौर पर अल्पसंख्यकों की शिकायतों के हवाले से भारत के खिलाफ नकारात्मक अभियान को भी जायज ठहराने की बात की गई है। इस वक्त जो क्षेत्रीय सामरिक माहौल है वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्तों के लिए नहीं है। अफगानिस्तान में पश्चिमी देशों की मौजूदगी खत्म होने के बाद भारत और पाकिस्तान में वहां दबदबा बनाने की होड़ और तेज होगी। नये समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे भी। जहां तक दक्षेस की बात है तो अभी इसके ठंडे बस्ते में रहने की संभावना है। इसमें तभी बदलाव होगा अगर अगला सार्क सम्मेलन पाकिस्तान से बाहर हो। कुल मिलाकर कहें तो भारत और पाकिस्तान के बीच किसी अर्थपूर्ण संवाद की संभावना बेहद कम है। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की बात है तो अतीत में पाकिस्तान को लेकर यू-टर्न के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह वो पाकिस्तान के नेता मोदी सरकार के लिए बोलते हैं। ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि मोदी के पास पाकिस्तान को लेकर किसी बड़े बदलाव के विकल्प ज्यादा मौजूद हों।

इन सब घटनाओं के बीच एक नई घटना सामने आई है जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। कोविड-19 जिससे बचने के उपाय हर देश करने लगा और भारतीय प्रधानमंत्री ने भी कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए सार्क (दक्षेस) देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया और सामूहिक प्रयास से एक सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड स्थापित किये जाने का प्रस्ताव रखा और इस फंड की रूपरेखा भी

तैयार की जाने लगी। इस माहौल में सार्क कोविड-19 आपातकालीन निधि के प्रबंधन में नेतृत्व को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद देखने को मिला है। पाकिस्तान में सार्क कोविड-19 आपातकालीन निधि में 3 मिलियन योगदान देने का वचन दिया है। साथ ही मांग की है कि इस पहल को सार्क संगठन के नियंत्रण में स्थापित करना चाहिए। भारत सरकार ने भी पाकिस्तान के इस निर्णय के बाद कहा कि महामारी से लड़ने में प्रत्येक सार्क सदस्य राष्ट्र की गंभीरता का अंदाजा उनके व्यवहार से लगाया जा सकता है। इस वातावरण में भी पाकिस्तान भारत का साथ देने को तैयार नहीं है।

पाकिस्तान ने हाल में हुए सार्क देशों के व्यापार अधिकारियों के आभासी सम्मेलन का बहिष्कार किया तथा भारत के नेतृत्व में किसी भी प्रकार के सहयोग करने से मना कर दिया। पाकिस्तान का मानना है कि कोविड-19 प्रबंधन की दिशा में कोई भी पहल नहीं प्रभावी हो सकती है। जब भारत के बजाय सार्क संगठन के सचिवालय द्वारा इस दिशा में सभी कार्यों का प्रावधान किया है।

लेकिन भारत सरकार का मानना है कि कोविड-19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित के लिए तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन सार्क सचिवालय मार्ग के माध्यम से कार्य करने में औपचारिकताओं का पालन करना होगा जबकि कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया निधि का गठन ही तुरंत कार्रवाई करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

भारत पर कई बार ये आरोप लगे हैं कि भारत अपनी मजबूत स्थिति का उपयोग कर सार्क देशों पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है। वर्तमान के अनिश्चितताओं के वातावरण में भारत के लिए एक जिम्मेदार पड़ोसी के रूप में अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन कर सार्क क्षेत्र के देशों के क्षेत्र में अपनी एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर है।

निष्कर्षतः

भारत और पाकिस्तान के विभाजन को 70 साल हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क हैं और पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि दोनों राष्ट्र राष्ट्रहित से सम्बंधित मसलों को समझें और उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। पाकिस्तान को भी समझना पड़ेगा कि उनकी सरजमीं से जो आतंकवाद की घटनाएं संचालित हो रही हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करे। व भारत और पाक दोनों को मिलकर अपने सम्बंधों को बेहतर बनाना होगा यदि सीमा पर शान्ति होगी तभी कश्मीर मसले का समाधान निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ-साथ ईरान-पाकिस्तान भारत पाइप लाइन जो मौजूदा वक्त में रुकी हुई है वो भी शुरू की जाएगी। जिससे दोनों राष्ट्रों की ऊर्जा की जरूरतों की पूर्ति होगी। इसके साथ-साथ सार्क, भारत और पाक के खराब सम्बंधों के कारण इसका आयोजन बीते दो वर्षों से नहीं हो पा रहा है। इनके सम्बंधों में अगर सुधार आएगा तो सार्क की कार्यवाही दोबारा से चालू की जाएगी।

अब समय आ गया है कि भारत सम्बन्धों को छोड़ते हुए विकास पर ध्यान केन्द्रित करें। दोनों देशों को अपने शत्रुतापूर्ण सम्बन्धों की कीमत आसियान, राष्ट्रमण्डल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर चुकानी पड़ रही है। दोनों इन मंचों पर एक-दूसरे की टांग-खिचाई की रणनीति बनाते रहते हैं। आशा है कि सार्क, शिखर सम्मेलन (इस्लामाबाद) के दौरान दोनों देशों में आई निकटता जेहादी मानसिकता पर आधारित आतंकवादी गतिविधियों एवं युद्ध की तैयारियों पर होने वाले अथाह धन का सदुपयोग लोगों के विकास की ओर उन्मुख करने का मार्ग प्रशस्त करें।

परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आतंक के भय का समूल अन्त नहीं होता तब तक देश में शान्ति व खुशहाली एक मृग मरिचिका के रूप में साबित होगी। पिछले पचास वर्षों से किये जा रहे उपाय निष्फल साबित हुए हैं। भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण सम्बन्ध को सुधारने के लिए विभिन्न रूकावटों के बावजूद भी शान्ति वार्ता व राजनीतिक संवाद को विराम नहीं दिया जाना चाहिए।

जरूरत है कि दोनों देशों को सामंजस्य और सद्भाव की भावना से विचार-विमर्श कर अपने विवादों को सुलझाना चाहिए। पाकिस्तान के साथ सम्बंध मधुर न होते हुए भी विश्व में फैली बीमारी के समय भारत ने किस तरह से सार्क देशों को आपस में जोड़ा और सहयोग करने की बात की।

संदर्भ ग्रंथ:-

- दीक्षित, जे. एन., भारत-पाक सम्बन्ध, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2003
- हरबीर सिंह, दक्षेस संघ लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ, बी. एस. शर्मा एंड ब्रदर्स, आगरा, 2003
- विश्व आभा, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की समस्यायें एवं सम्भावनायें, नारायण प्रकाशन, जयपुर, 2002
- **Bhattacharya, Dr. Sanchita, Indian Pakistan Relation : Saga Publication, 2016**
- **India Pakistan Relation : Border dispute "yerankor, Shriram, 2019**
- **India-Pakistan Composite dialogue process : issues and action, Padler, Sajad, 2018**
- **India and Pakistan continued conflict or Co-operation Wolpert Stanley A. 2014**
- **Indian Pakistan Relation" School of Inter study, J.N.U. 4 October, 2015**